भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः1131

उत्तर देने की तारीखः 08.02.2021

उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय

†1131श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' :

श्री कुंवर दानिश अली :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले, विशेषकर अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक चिह्नित किए गए जिलों के नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य सरकार, संसद सदस्यों और गैर-सरकारी संगठनों की ओर से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इन पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं होने के कारणहैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) कोशुरुकरना एक सतत प्रक्रिया है। साझा शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराते हुए मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैनिकों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान (आईएचएल) सहित स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय शुरु किए जाते हैं। नए केवी खोलने का प्रस्ताव तभी माना जाता है

जब इसे भारत सरकार के मंत्रालयों/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है और नए केवी स्थापित करने के लिए संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई जाती है। नए केवी कोशुरु करने के लिए विभिन्न प्रायोजन प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों को "चुनौती विधि" के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में 5 केवी, अर्थात्, नंबर 1 चकेरी कानपुर, नंबर 2 चकेरी कानपुर, नंबर 3 चकेरी कानपुर, आईआईटी,कानपुर और माटी अकबरपुर कार्यरत हैं।

(ग) केवीएस ने सूचित है कि पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में नए केवी की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार/संसद सदस्यों से कुल 10 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, भारत सरकार/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रायोजित प्रस्तावों और नया केवी स्थापित करने के लिए संसाधन प्रतिबद्धताओं पर ही विचार किया जाता है। प्राप्त 10 अनुरोधों में से, बिजनौर में एक नया केवी खोलने का केवल एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव में कुछ विसंगतियां/अपर्याप्तताएं देखी गईं, जिन्हें आवश्यक सुधार के लिए जिला प्रशासन बिजनौर, उत्तर प्रदेश के ध्यान में लाया गया है।

(घ) बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले से ही 21 केवी कार्यरत हैं।

*****